



2026:AHC:25190

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी सं. - 335 सन् 2026

रमेश चंद्र

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: संजय पांडे
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"1. प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश देने और निर्देश देने वाली परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 52-ए सपठित जोत चकबंदी नियमावली के नियम 109 के तहत मामला संख्या 19/12-13 (रमेश चंद्र बनाम राज्य) का निर्णय करें।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्रता से तय करने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।

4. उपरोक्त के रूप में इस निष्कर्ष में, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि रिट याचिका में उल्लिखित है, प्रतिवादी संख्या 2 को कानून के अनुसार एक तर्कपूर्ण और बोलने वाले आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को किसी भी अनावश्यक स्थगन को शीघ्रता से दिए बिना, अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर सख्ती से उपरोक्त मामले का निर्णय करने के निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंत में निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 5, 2026

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"